8% की दर से बढ़ा है।

लोगों की सेविंग बढ़ी है।

(प्रति व्यक्ति औसत आय रुपए में)

आर्थिक सर्वेक्षण 'एआइ-ओएस' पहल का दिया प्रस्ताव

एआइ को कॉरपोरेट से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाने की तैयारी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. दुनिया के बड़े देश एआइ में आगे निकलने के लिए महंगे और विशाल कंप्यूटर मॉडल बना रहे हैं लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 बताता है कि भारत ने इससे अलग रास्ता चुना है। सरकार एआइ को कुछ बड़ी कंपनियों की ताकत नहीं, बल्कि आधार और यूपीआइ की तरह सार्वजनिक सुविधा बनाने की तैयारी में है। इसी सोच के तहत 'एआइ-ओएस' का प्रस्ताव रखा गया है। यह एक सरकारी प्लेटफॉर्म होगा, जहां डेवलपर, रिसर्चर और स्टार्ट-अप मिलकर एआइ से जुड़े कोड और समाधान साझा कर सकेंगे। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, नियम और फंडिंग देगी, जबकि नए आइडिया नीचे के स्तर से निकलेंगे। मकसद है कि एआइ का फायदा सिर्फ चुनिंदा कंपनियों तक सीमित न रहे। प्रस्ताव है कि छात्र कक्षा 11 से ही अप्रेंटिसशिप और इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स के जरिए पढ़ाई के साथ काम करें और कमाई भी करें।

एआइ के दौर में भी इंसान की जरूरत: सर्वे यह भी बताता है कि एआइ के बावजूद कई क्षेत्रों में इंसानी काम की मांग बढ़ेगी। नर्सिंग, बुजुर्गों की देखभाल, सर्जरी, फिजियोथेरेपी, बिजली-तकनीशियन, शेफ और शुरुआती शिक्षा जैसे पेशों में आने वाले वर्षों में बड़े पैमाने पर रोजगार बन सकते हैं।

आइटी सेक्टर के लिए चेतावनी: सर्वे आइटी उद्योग को भी सतर्क करता है। अगर कंपनियां एआइ के साथ खुद को नहीं बदलतीं, तो भारत का पारंपरिक आउटसोर्सिंग मॉडल कमजोर पड़ सकता है।

छोटे एआइ मॉडल विकसित किए जाएं

सर्वे साफ कहता है कि भारत को अरबों रुपए खर्च कर बड़े भाषा मॉडल बनाने की दौड़ में नहीं पड़ना चाहिए। इसकी जगह ऐसे छोटे एआइ मॉडल विकसित किए जाएं, जो खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट जैसे खास क्षेत्रों की जरूरतें पूरी करें और मोबाइल या साधारण कंप्यूटर पर भी चल सकें। इससे बिजली, पानी और पैसे की भारी बचत होगी और तकनीक गांव-कस्बों तक पहुंचेगी। भले ही भारत एआइ की दौड़ में देर से आया हो, लेकिन उसके पास कुशल युवाओं के रूप में बड़ी ताकत है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे एआइ-साक्षर वर्कफोर्स है। यही वजह है कि विकेंद्रीकृत और कम-खर्च वाला एआइ मॉडल यहां काम कर सकता है।

ट्रांसफर पर खर्च करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए

चांदी चार लाख रुपए